प्रेस विज्ञप्ति

हमारे झारखण्ड प्रदेश में औद्योगिक विकास की प्रगति निराशाजनक

आज चेम्बर भवन में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित की गई जिसमें राज्य में निराशाजनक औद्योगिक विकास पर चेम्बर ने अपना रूख स्पष्ट किया।

चेम्बर अध्यक्ष रंजीत टिबडेवाल ने बतया कि झारखण्ड में औद्योगिक विकास के लिए सरकार मुम्बई, दिल्ली एवं विदेशों में पिछले 12 वर्षों से रोड शो और सेमिनार तथा दिल्ली में औद्योगिक मेला लगाते आ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 दिसम्बर को मुम्बई में झारखण्ड में शराब फैक्ट्री खोलने के लिए एक बैठक आयोजित की गई है। यह बडी चौंकानेवाली एवं दुखदायी भाग है। आश्चर्यजनक स्थिति है कि झारखण्ड में शराब फैक्ट्री के लिए सरकार मुम्बई में बैठकर योजना बनाने जा रही है, जबकि शराब फैक्ट्री को discourage करने की आवश्यकता है, उसके लाभ–हानि के बिना विचार किये हुए सरकार उसे बढावा देने के बारे में कैसे सोच सकती है ?

झारखण्ड का विकास झारखण्डी ही कर सकते हैं ना कि मुम्बई में बैठे विकास सलाहकार और विदेशों में बैठकर या रोड शो करके विकास कर सकते हैं। सरकार ने पिछले 12 वर्षों में कभी भी झारखण्ड वासियों से विकास एवं औद्योगिकिकरण पर चर्चा नहीं की है। शायद यहॉ के नेताओं एवं अधिकारियों को यह ज्ञान नहीं है कि विकास का लाभ एवं दंश भी यहीं के लोगों को झेलना है। मुम्बई में बैठकर विकास की योजनाएँ बनाना निराशाजनक है जबकि यहॉ फेडरेशन चेम्बर एवं जेसिया जैसे राज्यस्तरीय संस्थान हैं जिनमें झारखण्ड को दिशा एवं दशा देने की क्षमता है।

हमने सुना है कि महुआ से स्प्रिट उत्पादन नहीं होगा, जबकि techniqually जहॉ तक मुझे जानकारी है महुआ से सिर्फ चुलाई शराब बन सकता है। बिहार में महुआ नीति बन गई है जिसका उपयोग शराब या चुलाई में नहीं हो सकता है। महुआ सिर्फ cattle feed के उपयोग में लाया जा सकता है। स्प्रिट का निर्माण चावल, जौ एवं moulisus छबुआ में होता है। झारखण्ड में अगर स्प्रिट उत्पादन का लाईसेन्स दिया जायेगा तो जगजाहिर है कि इससे मनुष्य के खाने की वस्तुएँ चावल एवं जौ की किल्लत होगी एवं महॅगाई और भी अत्यधिक बढेगी।

बिना नई पर्चेस पॉलिसी लाये हुये पर्चेस पॉलिसी 2007 को निरस्त कर दिया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण एवं बाहर के लोगों को कार्यादेश देने की साजिश है और यहॉ के व्यवसायियों एवं उद्यमियों को deprive किया जा रहा है।

सिंग्ल विंडो सिस्टम एक्ट अभी तक फाईलों में ही दफन है। दर्जनों बैठकें हो चुकी हैं लेकिन अभी तक उसे उतारा नहीं गया। 12 वर्षों से सरकार को यह चिंता नहीं है कि यहॉ के व्यवसायियों एवं उद्यमियों से बैठकर उचित विचार–विमर्श किया जाय अथवा समीक्षा की जाय कि क्या वर्तमान उद्योगों को कठिनाई है तथा उनका विकास कैसे किया जाय ?

उद्योग विभाग के उद्योग निदेशक छुट्टी में बार–बार कभी चुनाव ड्यूटी में चली जा रही हैं। मैं समझता हूॅ कि वर्ष में 6 महीने उद्योग निदेशालय, बिना उद्योग निदेशक के कार्य कर रहा है।

रियाडा के बोर्ड की बैठक पिछले 1 वर्ष से नहीं हो रही है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कैसे औद्योगिक विकास झारखण्ड में होगा ? यह समझ से परे है कि सरकार आयातित सामानों से झारखण्ड का विकास कैसे कर लेगी ?

फेडरेशन चेम्बर राज्य सरकार से यह मॉग करता है कि विकास की योजनाऍ यहॉ के व्यवसायियों एवं उद्यमियों से प्रमुख रूप से फेडरेशन चेम्बर एवं जेसिया जैसे सलाहकार से अर्जित करे, तभी राज्य का विकास सम्भव है। यहॉ Usha Martin, H.E.C., MECON, TATA Steel, Jindal जैसे अनेकों संस्थाऍ है, जिन्होंने विदेशों में काफी ख्याति प्राप्त की है। यहॉ ट्रेड, इन्डस्ट्री में भरपूर मात्रा में इंजीनियर एवं अनुभवी व्यक्ति हैं।

जेसिया के उपाध्यक्ष शरद पोद्दार ने कहा कि सरकार के पत्र के अनुसार नई क्रय नीति अक्टूबर 2012 तक लागू हो जानी चाहिए थी। अभी सरकारी खरीद की प्रक्रिया चरम पर है तथा क्रय नीति में जानबूझ कर विलम्ब किया जा रहा है ताकि झारखण्ड से बाहर से माल का क्रय किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि उद्योग नीति 2012 में कई विषमताऍ हैं जैसे–कैपिटल सब्सिडी नहीं के बराबर है, वैट सब्सिडी में इतनी जटिलताऍ हैं कि यहॉ के उद्यमी कभी भी लाभ नहीं ले सकेंगे। साथ ही इस पॉलिसी में इन्ट्रेस्ट पर सब्सिडी का कहीं प्रावधान नहीं है। विस्तारीकरण में सब्सिडी के प्रावधान इतने अव्यवहारिक हैं कि उद्यमी इसका लाभ कभी नहीं ले सकेंगे। निर्यात पर आधारित उद्योग, फूड प्रोसेसिंग उद्योग एवं टेक्सटाईल उद्योग को बढावा देने के लिए भी कोई स्पष्ट लाभ इस नीति में नहीं है। ये सारी विषमताऍ माननीय मुख्यमंत्री के साथ राज्यस्तरीय बैठक में 30 सितम्बर 2012 को बताया गया था जिसपर माननीय मुख्यमंत्री ने एक समिती बनाकर इसे दूर करने की बात कही थी। ढाई महीने के बाद भी ऐसी कोई समिति का गठन नहीं हो सका है जिससे सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं !

इस संवाददाता सम्मेलन में चेम्बर अध्यक्ष रंजीत टिबडेवाल, महासचिव प्रदीप कुमार जैन, जेसिया के उपाध्यक्ष शरद पोद्दार एवं चेम्बर के कार्यकारिणी सदस्य प्रेम कटारूका भी मौजूद थे।

प्रदीप कुमार जैन
महासचिव

पत्रांकःएफ.जे.सी.सी.आई / 2012.13 दिनांकः 24.11.2012

सभी प्रेस को प्रकाशनार्थ प्रेषित।